ये मूल्य सारे देश में समान हैं। स्टेट और कम्पलेक्स दोनों फास्फेटिक उर्वरक के मूल्य सांविधिक रूप से नियंत्रित नहीं हैं। तथापि मार्च, 1976 से लागू मूल्य समर्थन योजना के अनुसार सरकार म्पलैक्स उर्वरकों के अधिकतम विक्रय मूल्य निर्धारित कर रही है। विद्यमान अधिकतम विक्रय मूल्य बता े वाला विवरण पत्र सभा तटल पर रखा गया। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—51 77] विभिन्न नि ातिाओं द्वारा निर्मित सिंगल सुपर-फास्फेट का अधिकतम विक्रय मूल्य फर्टिलाइजर एसोसिएशन आफ इंडिया द्वारा इस सूत्र (फार्मूला) जिसे सरकार क अनुमोदन प्राप्त था, के अनुसार निर्धारित िए गए हैं।

(ख) देश के अधि तम वाणिज्यिक हित के लिए विभिन्न स्त्रोतों से आयातित किए गये रासायनिक उर्वरकों के दर का बताना उचित नहीं समझा गया है। भाग (क) के उत्तर में बताए गए नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों अर्थात् यूरिया अमोनियम सल्फेट तथा कैल्सियम अमोनियम के मूल्य सांविधिक रूप से निर्धारित मूल्य हैं। अन्य आयातित स्ट्रेट और कम्पलैक्स उर्वरकों के मूल्य समय समय पर कृषि मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। प्रचलित मूल्य सभा पटल पर रखे गए विवरण में दिखाए गए हैं। [ग्रन्था य में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०—51/77]

राजस्थान में नई रेल लाइनें

10. **श्री मीठा लाल पटेल : क्या रेल मंत्री** य बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान मे कितनी नई रेल लाइनें बिछाने का विचार है ;

(ख) क्या इन तथ्यों के बावजूद राज्य में नई रेल लाइनें नहीं बिछायी जा रही हैं जबकि अनेक नई रेल लाइनों के लिए सर्वेक्षण किया जा चुका है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और किन-किन रेल लाइनों के लिए सर्वेक्षण किया जा चुका है और क्या उन रेल लाइनों पर आने वाली कुल लागत सहित सर्वेक्षण प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखा जाएगा ; और

(ग) क्या जिन लाइनों का सर्वेक्षण हो चुका है उन में करौली होकर जाने वाली धौलपुर-गंगापुर सिटी लाइन शामिल नहीं है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या भविष्य में इस लाइन का सर्वेक्षण किया जायेगा, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) राजस्थान में पड़ने वाली डावला-सिंध ा लाइन के निर्माण का काम पांचवी योजना के दौरान पहले ही पूरा हो चुका है। इस समय राजस्थान में न तो कोई दूसरी नयी लाइन निर्माणाधीन है और न निर्माण के लिए अनुमोदित की गयी है। चूंकि सम्पूर्ण 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नयी रेलवे लाइनों का काम हाथ मे लेने संबंधी प्रस्तावों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है इसलिये यह कहना मुश्किल है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना की बकाया अवधि में राजस्थान में किसी नयी रेलवे के लाइन निर्माण का काम हाथ में लिया जायेगा।

(ख) राजस्थान में निम्नलिखित नयी लाइनों के संबंध मे सर्वेक्षण हाल में पूरे किये

चा चुके हैं अथवा प्रगति पर हैं :—

लाइन का नाम	लम्बाई (कि० मी० में)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपयों में)	वर्तमान स्थिति
1. रतलाम-बांसवाड़ा (I) मार्ग . .	1—78.76	24.55	सर्वेक्षण पूरे किये जा चुके हैं और सर्वेक्षण रिपोर्टों और अनुमानों की जांच की जा रही है।
नयी बड़ी लाइन (II) मार्ग . .	11—95.13	34.26	
2. नाथद्वारा—पालना . नयी मीटर लाइन	190	उपलब्ध नहीं है	इंजीनियरी-एवं यातायात सर्वेक्षण प्रगति पर है।

उपर्युक्त लाइनों को बनाने का काम शुरू करने के बारे में अंतिम निर्णय सभी दृष्टिकोणों से सर्वेक्षण-रिपोर्टों की जांच पूरी हो जाने तथा धन की उपलब्धता को ध्यान मे रखते हुए किया जायेगा।

नयी लाइन परियोजनाओं की सर्वेक्षण रिपोर्टें तकनीकी प्रकृति की होती है और केवल विभागीय उपयोग के लिये ही होती है, आमतौर पर, ये रिपोर्टें सभा पटल पर नहीं रखी जाती है।

(ग) इस लाइन के लिए कोई सर्वेक्षण नही किया गया है। वर्तमान कठिन वित्तीय स्थिति के कारण निकट भविष्य में इस लाइन के सर्वेक्षण एवं निर्माण का काम शुरू करना रेलों के लिए कठिन होगा।

सतना से बरास्ता रीवा ब्योहारी तक रेल लाइन

11. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य रेलवे ने सतना रेलवे स्टेशन से बरास्ता रीवा ब्योहारी तक नई रेल लाइन का निर्माण करने का प्रस्ताव, 1972,1973 और उससे भी पूर्व प्रेषित किया था जिससे कि यह नई लाइन सिंगरौली-कटनी के रास्ते ब्योहारी को जोड़ सके ; और

(ख) क्या रीवा नगर के महत्व और अत्यन्त पिछड़े क्षेत्र के विकास को देखते हुए सरकार का विचार पांचवी पंचवर्षीय योजनावधि में उक्त रेल लाइन का निर्माण करने का है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) जी हां,

(ख) 1973 के दौरान सतना से ब्योहारी तक एक शाखा लाइन के लिए किये गये सर्वेक्षण से पता चला कि इस परियोजना से मचेष्ठ यातायात नहीं होगा तथा यह वित्तीय दृष्टि से सक्षम नहीं होगी और इसलिये परियोजना को छोड़ दिया गया। 1973 के दौरान किये गये सर्वेक्षण के आधार पर सतना से रीवा तक की कम लम्बाई में लाइन के लिए पुनर्मूल्यांकन किया गया है। संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए सभी दृष्टिकोणों से रिपोर्ट की जांच कर लिये जाने